IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE VIVEK AGARWAL

ON THE 28th OF FEBRUARY, 2025

WRIT PETITION No. 3428 of 2025

SMT.MUNNI @ MADHURI TIWARI

Versus

THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS

Appearance:

Shri Sanjeev Kumar Singh - Advocate for the petitioner.

Shri Jitendra Shrivastava - Panel Lawyer for the respondents-State.

ORDER

This petition is filed by petitioner - Smt. Munni @ Madhuri Tiwari being aggrieved of the order dated 21.10.2024 (Annexure P-4) passed by the Collector and District Magistrate, Umariya in case No.11/Jila Badar/2024, whereby the petitioner was directed to be externed from the boundaries of District Umariya and the neighbouring districts for a period of one year. This order has been affirmed by the Divisional Commissioner, Shahdol Division, Shahdol vide order dated 20.01.2025 (Annexure P-9) passed in case No.142/Appeal/2024-25.

2. Shri Sanjeev Kumar Singh, learned counsel for the petitioner submits that only a list of 6 cases has been shown to be pending against the petitioner. She has not been convicted in any of the cases. Two of the cases are under Section 110 of the Cr.P.C., 2 under Sections 294, 323, 506, 34 of IPC and 2 under the provisions of the NDPS Act.

3. Shri Jitendra Shrivastava, learned Panel Lawyer, in his turn, supports the

Signature Not Verified
Signed by: PUSHPENDRA PATEL
Signing time: 3/7/2025 6:51:19 PM

impugned orders and submits that looking to the criminal activities of the petitioner, order of externment has been passed taking into consideration the provisions as contained in Section 5(a) and 5(b) of the Madhya Pradesh Rajya Suraksha Adhiniyam, 1990 (for brevity "Adhiniyam of 1990").

4. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, Section 5 of the Adhiniyam of 1990 provides for removal of persons about to commit offence. Section 5(a) reads as "that the movements or acts of any person are causing or calculated to cause alarm, danger or harm to person or property'". Section 5(b) reads as "that there are reasonably grounds for believing that such person is engaged or is about to be engaged in the commission of an offence involving force or violence or an offence punishable under Chapter XII, XVI or XVII or under Section 506 or 509 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) or in the abatement of any such offence, and when in the opinion of the District Magistrate witnesses are not willing to come forward to give evidence in public against such person by reason of apprehension on their part as regards the safety of their person or property;"

5. Thus, it is evident that the requirement of Section 5(a) is that the movements or acts of any person should cause alarm, danger or harm to person or property. Sub-section (b) of Section 5 provides that there should be reasonable grounds of engagement of such person in commission of an offence mentioned therein and then the District Magistrate should form an opinion that witnesses are not willing to come forward to give evidence in public against such person by reason of apprehension on their part.

Signature Not Verified
Signed by: PUSHPENDRA PATEL
Signing time: 3/7/2025 6:51:19 PM

6. In the cross-examination of the sole witness, namely, Shri Madan Lal Maravi S/o Bhura Prasad Maravi, SHO, Police Station - Pali, District Umariya, it has been note as under:-

"**<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अनावेदिका अधिवक्ता श्री तरूण कुमार पाण्डेय</u>** :- यह कहना सही है कि सुधा तिवारी पति प्रदीप तिवारी के विरूद्ध NDPS का केश चलता है। स्वतः कहा कि सुधा तिवारी अनावेदिका गुन्नी तिवारी उर्फ माधुरी तिवारी की बहन है। में नहीं बता सकता कि चंद्रभान शर्मा के पुत्र दीपक शर्मा के विरूद्ध NDPS का केश चलता है। यह कहना राही है कि चंद्रभान शर्मा के पुत्र दीपक शर्मा के विरूद्ध आर्म्स एक्ट का मामला पाली न्यायालय में विचाराधीन है। यह कहना सही है कि प्रदीप तिवारी एवं उसका परिवार तथा चंद्रभान शर्मा एवं उसका परिवार आपराधिक गतिविधियों में रालम्म है। यह कहना यही है कि थाना पाली के प्रतिवेदन के बिन्दु क्र. 02. में जिरा अपराध का लेख है कि उस अपराध में आरोपी रमेश सिंह सेंगर के बयान के आधार पर माधुरी तिवारी उर्फ मुन्नी को आरोपी बनाया गया था उरासे कोई भी मादक पदार्थ जप्त नहीं हुआ था। मैं आज यह नहीं बता सकता कि अनावेदिका माधुरी तिवारी उर्फ मुन्नी किसी भी अपराध में दोषसिद्ध हुयी है या नहीं। यह कहना सही है कि जो व्यक्ति अपराध करता है वह अपराध उसी के लिये होता है। स्वत: कहा कि कुछ मागलो में अप्रत्यक्ष रूप से अन्य आरोपियों का सहयोग रहता है। यह कहना सही है कि अनावेदिका माधुरी तिवारी उर्फ मुन्नी तिवारी के पति राजेन्द्र तिवारी एवं लडकी बरखा पाण्डेय के बारे प्रतिवेदन में लेख किया है। स्वतः कहा कि अनावेदिका के साथ उसका पति एवं लडकी रहती है। में आज नहीं बता सकता कि अनावेदिका के पति राजेन्द्र तिवारी एवं पुत्री बरखा तिवारी किस मामलो में दोषमुक्त हुये है। यह कहना गलत है कि प्रतिवेदन में जिन अपराधों का लेख किया है उन अपराधों में अनावेदिका के पति एवं पुत्री दोषमुक्त हो चुके है। यह कहना सही है कि अनावेदिका के विरूद्ध कभी भी बलवा या शांति भंग तथा राजद्रोह करने का अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ है। यह कहना सही है कि अनावेदिका के विरूद्ध शरीर संबंधी गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। यह कहना राही है कि पुलिस अधीक्षक महोदय उमरिया को प्रतिवेदन देने के पूर्व थाना पाली द्वारा जारी अनावेदिका को चनेई नोटिस नहीं दिया है तथा कोई जवाब भी नहीं लिया है। यह कहना गलत है कि में प्रतिवेदन में जो गंभीर चोट के संबंध में अपराध करना बताया है उसके संबंध में कोई भी अपराध अनावेदिका के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध नहीं है। स्वतः कहा कि अप.क्र. 527/23 धारा 294, 323, 325, 506, 34 आईपीसी पंजीबद्ध है। यह कहना सही है कि गैने पाली थाना अंतर्गत किसी भी ऐसे व्यक्ति का कथन लेख नहीं किया है जिसने यह बताया हो कि अनावेदिका द्वारा दिये गये मादक पदार्थ (गांजा) का सेवन करने से उसे मानसिक, आर्थिक व वैज्ञानिक क्षति हुयी हो। यह कहना गलत है कि अनावेदिका को पुलिस थाना पाली द्वारा जबरन दो NDPS का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। यह कहना सही है कि इस मामले में गेने पाली क्षेत्र अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का ऐसा कोई कथन लेख नहीं किया है कि आम जनता व युवाओं के माता-पिता व परिजन अत्यधिक भयभीत रहते है जिसका समाज में स्वछंद रहना समाज में अहितकर रहना व परिशंकटमय हो गया हो। यह कहना सही है कि अनावेदिका के विरूद्ध पुलिस के साथ झगडा करना व विवाद करने के अपराध पंजीबद्ध नहीं है। यह कहना सही है कि अनावेदिका के विरूद्ध ऐसा कोई अपराध पंजीबद्ध नही है जिसमें वह सामाजिक, संगठन के विरूद्ध या समुदायी के विरूद्ध अपराध किया हो। यह कहना सही है कि इस मामले में किसी व्यक्ति का ऐसा कोई कथन लेख नहीं किया है जिसने यह बताया हो कि पाली क्षेत्र अंतर्गत समाज का नव युवक नशे के आगोश में आकर भविष्य अंधकार मय हो रहा है। में आज यह नहीं बता सकता कि अनावेदिका की उम्र 51 वर्ष है या उससे ज्यादा है। में आज नहीं बता सकता कि अनावेदिका का पति बीमार (हृदय रोग) रहता है। मै आज उम्र संबंधी दस्तावेज के बिना नहीं बता सकता कि अनावेदिका के पति की उम्र 70 वर्ष का है तथा उनकी देखरेख अनावेदिका ही करती है। स्वतः कहा कि दोनो चल फिर सकते है दोनो पति-पत्नी यहां-वहां आ-जा सकते है। यह कहना गलत है कि गलत तथ्यों के आधार पर अनावेदिका के विरूद्ध जिलाबदर का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। यह कहना गलत है कि प्रतिवेदन देने के पूर्व अनावेदिका द्वारा पुलिस थाने में पदस्थ महेश मिश्रा, तारा सिंह

Signature Not Verified
Signed by: PUSHPENDRA PATEL
Signing time: 3/7/2025 6:51:19 PM

एवं प्रमोद जाटव के विरूद्ध लिखित शिकायत दी गयी थी। यह आरोप गलत है कि अनावेदिका द्वारा उन तीनों के विरूद्ध पुलिस महानिरीक्षक शहडोल के समक्ष तीनो व्यक्तियों द्वारा पैसा गांगने की शिकायत की गई थी। यह कहना गलत है कि में दबाव बनाने एवं शिकायत वापस लेने के लिये जिलाबदर का प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय को प्रेषित किया है। यह कहना सही है कि अनावैदिका का सुनवाई का कहा कि जिलाबदर प्रतिवेदन प्रस्तुत प्रस्तुत करने के बाद माननीय बिना पुलिस अधीक्षक को जिलाबदर का प्रतिवेदन प्रेषित किया था। स्वतः कहा कि अवसर दिये बिना कलेक्टर न्यायालय द्वारा अनावेदिका की सुनवाई होती है।"

7. Thus, it is evident that SHO Shri Madan Lal Maravi whose statements were recorded by the Collector and which have been relied on by Shri Jitendra Shrivastava, learned Panel Lawyer after opening of the record and is accepted to be the only person whose statements were recorded by the District Magistrate, Umariya, reveals certain glaring facts, namely, in case No.223/2022, petitioner was impleaded as an accused on the basis of statements of accused Ramesh Singh Senger and no contraband substance was seized from her. Similarly, he has admitted that it is true to say that in Pali region, none of the persons has given statement that the public or the youth or their parents or their relatives are under such a grievous threat that there will be problem to their existence, if petitioner is allowed to remain free. This witness has also admitted that no report was received against the petitioner of causing *Jhagda* or dispute with the police personnel and further admitted that no such case is registered against the petitioner which may be against the society, organization or the community. He has further admitted that he had not recorded statements of any person whose future may become dark under the influence of contraband substances.

8. Thus, it is evident that Collector, Umariya passed an order dehors the requirements of Section 5(b) of Adhiniyam of 1990. It appears that the order of externment has been passed merely on certain other compulsions than the

Signature Not Verified
Signed by: PUSHPENDRA PATEL
Signing time: 3/7/2025 6:51:19 PM

requirements of law. Evidence of Madan Lal Maravi is crystal clear. It does not inspire confidence to existence of any material so to fulfill the requirements of Sections 5(a) and 5(b) of the Adhiniyam of 1990.

9. It is unfortunate that even the Divisional Commissioner, Shahdol, Division Shahdol has chosen to not to apply her mind to the fact and circumstances of the case and has merely countersigned an order of rejection of appeal, without application of mind.

10. This is a serious matter. Divisional Commissioners are supposed to apply their mind when appeals are filed before them under the provisions of any Act. They cannot be allowed to act as a post office. Perusal of impugned order (Annexure P-9) passed by the Divisional Commissioner reveals that there is absolutely no appreciation of either the legal provisions contained in Sections 5(a) and 5(b) of the Adhiniyam of 1990, nor the material which was available on record, especially, the prosecution evidence in the form of statements of Madan Lal Maravi, SHO. Therefore, both the orders dated 21.10.2024 (Annexure P-4) passed by the Collector and District Magistrate, Umariya and dated 20.01.2025 (Annexure P-9) passed by the Divisional Commissioner, Shahdol Division, Shahdol, being cryptic and arbitrary and appearing to be an attempt on behalf the mighty State to curtail the personal freedom of an individual, are hereby quashed.

11. Respondent-State shall bear the cost of this litigation which is quantified at Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand only) which will be payable to the petitioner by the Collector, Umariya. Let this cost be paid to the petitioner within 7 days from the date of communication of this order.

Signature Not Verified
Signed by: PUSHPENDRA PATEL
Signing time: 3/7/2025 6:51:19 PM

12. In above terms, the writ petition is allowed and disposed of.

(VIVEK AGARWAL)
JUDGE

pp

Signature Not Verified
Signed by: PUSHPENDRA PATEL
Signing time: 3/7/2025 6:51:19 PM